© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 03 , Issue : 10 | October – December 2017

राजस्थान की निर्वाचकीय राजनीति में बसपा का उभार एवं संभावना

गजेंद्र सिंह , असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभागए राजस्थान विस्वविद्यालयए जयपुर

सारांश :
राजस्थान में लंबे समय तक कोई भी दल कांग्रेस व भाजपा के विकल्प के रूप में नहीं उभरा है जबकि भारत के अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल काफी प्रभावी एवं फल–फूल रहे हैं। बसपा पिछले तीन दशकों से राजस्थान में अपने आप को स्थापित करने व तीसरी शक्ति बनने के लिए संघर्षरत है। इस शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान की निर्वाचकीय राजनीति में बसपा की भूमिका व उसकी संभावनाओं का विश्लेषण करना है।

मुख्य शब्द :
बर्हिवंशी राजनीति, समावेशी राजनीति, सामाजिक अभियांत्रिकी, बामसंफ, ध्रुवीकरण।

प्रस्तावना :

बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम अनुसूचित जाति वर्ग में चमार जाति से थे। काशीराम का जन्म 1934 में उत्तर भारत के पंजाब प्रान्त में हुआ। बी.एस.सी. की डिग्री करने के बाद काशीराम ने पुणे में शोध प्रयोगशाला में सरकारी नौकरी में प्रवेश लिया।

यद्यपि आरम्भ में काशीराम का राजनीतिक जीवन की ओर रूझान नहीं था। संयोगवश सरकारी सेवा में जातीय भेदभाव ने उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया। डॉ. बी.आर. अम्बेड़कर के जन्म दिन पर सरकारी अवकाश की मांग लेकर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने आन्दोलन किया। इस आन्दोलन में काशीराम ने भी भाग लिया। इस कारण उन्हें नौकरी से निलम्बित कर दिया गया। उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और 1978 में आल इंडिया बैकवर्ड्स एण्ड माइनारिटीज कम्यूनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन (बामसेफ) की स्थापना की। बामसेफ कर्मचारी का संगठन था जो दलित वर्ग के राजनीतिक प्रभाव की बढ़ोतरी से प्रेरित था।

आरम्भ में बामसेफ ने रिपब्लिक पार्टी की गतिविधियों का समर्थन किया जो भारत की प्रमुख दलित पार्टी के रूप में जानी जाती थी और जिसका आधार मुख्य रूप से महाराष्ट्र था। 1981 में काशीराम ने दलित शेषित समाज संघर्ष समिति (डी एस–4) का गठन कर सीधे राजनीतिक सहभागिता कर दलितों को आकर्षित किया। 1984 में काशीराम ने औपचारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी के रूप में नई पार्टी का गठन किया। बामसेफ ने आरम्भ में "बसपा का पर्याप्त आधारभूत समर्थन प्रदान किया। बसपा का सर्वोच्य लक्ष्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था। काशीराम के अनुसार राजनीतिक सत्ता "मास्टर चाबी" है। जिससे आप किसी भी ताले को खोल सकते हैं। चाहे यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या सांस्कृति ताला हो।"

संगठन एवं रणनीति :

बसपा ने सर्पप्रथम उत्तर प्रदेश फिर उत्तर भारत एवं इसके बाद दक्षिण भारत में विस्तार की योजना बनायी। उत्तर प्रदेश में बसपा ने 1995, 1997, 2002–03 में तीन बार अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई वही 2007–12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 1984 से 2003 तक बसपा बर्हिवंशी राजनीतिक विचार पर चली जिसका उद्देश्य दलितों को बसपा के पक्ष में ध्रुवीकृत करना था जबकि 2003 के बाद समावेशी राजनीति अपनाई जिसके तहत अन्य जातियों को बसपा के साथ जोड़ना था। 2003 से ही बसपा ने समाजिक अभियांत्रिकी के तहत ब्राह्मण समाज को बसपा से जोड़ा। उत्तर प्रदेश से बाहर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी अब बसपा का संगठन विस्तार हो गया है।

राजस्थान में बसपा का विस्तार और प्रभाव :

राजस्थान की दलीय व्यवस्था में कांग्रेस और भाजपा दो महत्वपूर्ण ध्रुव हैं। भारत के अधिकांश राज्यों से भिन्न यहाँ पर पिछड़े दो दशकों में तीसरी ताकत नहीं उभरी है। लेकिन दलित पार्टी के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बना चुकी बहुजन समाज पार्टी की संभावनाएँ यहां तीसरी ताकत के रूप में दिखाई देती हैं। चूंकि भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के समर्थन का आधार विचारधारागत कम और जाति आधारित अधिक है। भारतीय समाज में अनुसूचित जाति सभी जगह पाई जाती है। बसपा अपनी इसी दलित पहचान के आधार पर राजस्थान में अपने प्रभाव के विस्तार में निरन्तर प्रयत्नशील बसपा ने अपने गठन के 5 वर्ष बाद 1989 में राजस्थान में राज्य इकाई का गठन किया। गठन के लगभग एक दशक तक बसपा का प्रादेशिक संगठनात्मक ढ़ांचा ढ़ीला–ढ़ाला, सीमित व कमजोर ही रहा। किन्तु उत्तर प्रदेश की प्रारिम्भ सफलताओं से उत्साहित होकर बसपा ने राजस्थान में संगठनात्मक निवेश को बढ़ाया।

कांग्रेस बसपा के विस्तार से अधिक सजग दिखाई देती है। क्योंकि राजस्थान में अनुसूचित जाति को कांग्रेस के समर्थन का परम्परागत आधार माना जाता रहा है। यद्यपि आरमभ में बसपा नेतृत्व का ध्यान राजस्थान की ओर अपेक्षाकृत कम

ही रहा, किन्तु पिछले एक दशक से बसपा ने राजस्थान में अपने प्रभाव के विस्तार हेतु अधिक ध्यान दिया है और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र स्तर तक अपने संगठनात्मक ढ़ांचे को मजबूत किया है। भारतीय समाज में बसपा ने प्रारम्भ में बर्हिवेशी राजनीति कर दलितों को ध्रुवीकृत करने की राजनीति के चलते प्रारम्भ में बसपा राजस्थान में अपना विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई किन्तु 2002 के बाद बसपा ने बर्हिवेशी राजनीति को त्याग कर अन्य जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए समावेशी राजनीति का उत्तर प्रदेश में विशेष प्रयोग किया। बसपा की इस नीति के कारण उसकी दलित कट्टरपंथी पार्टी की पहचान की धार अपेक्षाकृत कमजोर हुई। बसपा ने अपनी इस समावेशी राजनीति का प्रयोग राजस्थान में भी किया जिससे उसको लाभ मिला और अपने प्रभाव में अपेक्षाकृत सकारात्मक वृद्धि की।

राजस्थान में बसपा के निरन्तर बढ़ते प्रभाव से तीन महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होते है। प्रथम, राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में बसपा की क्या सम्भावनाएँ हैं। द्वितीय, बसपा के बढ़ते प्रभाव से राजस्थान की दलीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, राजस्थान की दलीय व्यवस्था के दो ध्रुव–कांग्रेस व भाजपा में से बसपा का विस्तार किस दल के लिए घातक होगा।

राजस्थान में बसपा की संभावनाओं के आंकलन के लिए पिछले निर्वाचकीय परिणामों पर दृष्टिपात करने पर बेहत रोचक तथ्य सामने आते हैं। विधान सभा में निर्वाचन में बसपा की बढ़ती प्रभावशीलता को सारणी–3.1 में दर्शाया गया है।

सारणी – 3.1 : विधानसभा में बसपा की प्रभावशीलता

निर्वाचन वर्ष	प्रत्याशियों की संख्या	विजयी सीट	कुल प्राप्त मत प्रतिशत	निर्वाचन सीटों से प्राप्त मत प्रतिशत
1990	57	0	0.79	2.54
1993	50	0	0.56	2.01
1998	108	2	2.17	3.81
2003	124	2	3.97	6.40
2008	199	6	7.60	7.66
2013	199	3	3.37	3.48

स्त्रोत–राज्य निर्वाचन विभाग से संकलित विभिन्न वर्षों के आंकड़ों के आधार पर।

राजस्थान में बसपा की संभावनाओं को निर्वाचन में उसकी प्रभावशीलता के द्वारा आंकलन करने का प्रयास किया है। निर्वाचन में बसपा की प्रभावशीलता के विश्लेषण के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, बसपा ने कितनी विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ा। द्वितीय कितनी सीटों पर विजयी रही। तृतीय, कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया और चतुर्थ, चुनाव लड़ी गई सीटों पर कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया।

अपने गठन के बाद बसपा ने सर्व प्रथम 1990 के विधान सभा निर्वाचन में भागीदारी की और 57 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे। 1993 के विधान सभा निर्वाचन में 50, 1998 के निर्वाचन में 108, 2003 के निर्वाचन में 124 और 2008 एवं 2013 के निर्वाचन में 199 सीटों पर चुनाव लड़ा। आरम्भ में सभी सीटों पर निर्वाचन में प्रत्याशी न उतारना यह दर्शाता है कि 1990 के दशक में राजस्थान में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा व्यापक नहीं था और केवल सीमित स्थानों पर ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे।

राजस्थान विधान सभा निर्वाचन में बसपा के प्रत्याशियों की संख्या क्रमिक चुनावों में बढ़ती गई और 2008 के निर्वाचन में यह संख्या 200 हो गई। हालांकि एक सीट पर प्रत्याशी की निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने पर पार्टी ने 199 सीटों पर चुनाव लड़ा। राजस्थान में कांग्रेस व भाजपा के अलावा बसपा तीसरी ताकत थी जिसने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इससे यह स्वभाविक निष्कर्ष निकलता है कि पार्टी का पूरे प्रदेश में एक संगठनात्मक ढ़ांचा तैयार हो गया है कि पार्टी का पूरे प्रदेश में उसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। जहां तक विजयी सीटों का सवाल है तो 1990 व 1993 के प्रथम दो निर्वाचनों में बसपा को कोई सीट नहीं मिली। किन्तु 1998 के निर्वाचन में बसपा ने सर्वप्रथम दो सीटें जीती और राजस्थान विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2003 में सम्पन्न 12वीं विधानसभा में बसपा ने अपनी पूर्व की स्थिति को कायम रखा। 2008 के 13वीं विधानसभा निर्वाचन में बसपा ने विधानसभा ने अपनी संख्या में तीन गुपा वृद्धि दर्ज की। बसपा के 6 प्रत्याशी निर्वाचित हुए और 10 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। 2013 के विधानसभा चुनावों में मोदीलहर के बावजूद 3 सीटे जीती जबकि पाँच सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे।

लेकिन किसी दल की प्रारम्भिक अवस्था में उसकी प्रभावशीलता व संभावनाओं के आंलन के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसने निर्वाचन में कितनी सीटें जीती हैं बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि उसने कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है और जिन सीटों पर चुनाव लड़ा है उन पर कितने प्रतिशत मत मिले हैं। बसपा ने राजस्थान में अपने शुरूआती दौर में सीमित प्रत्याशी मैदान में उतारे और कुल मतों का एक प्रतिशत से कम तथा मुकाबले वाली सीटों पर दो प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किये। 19998 में बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कुल मतों का दो प्रतिशत से अधिक तथा मुकाबले वाली सीटों पर

लगभग चार प्रतिशत समर्थन प्राप्त किया। 12वीं व 13वीं विधानसभा निर्वाचन में यह समर्थन बढ़ा और 13वीं विधानसभा में पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़कर कुल मतों का 7.6 प्रतिशत समर्थन प्राप्त किया और पार्टी ने तीसरी व निर्णायक शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई चौदहवीं विधानसभा चुनावों में प्रचण्ड मोदीलहर के बावजूद 3.48 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीन सीटें जीती। प्रदेश में बसपा के संगठनात्मक आधार व समर्थन का न्यूनतम स्तर, जो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, के आधार पर यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि बसपा राजस्थान में निर्णायक ताकत के रूप में उभर रही है और उसकी महत्वपूर्ण संभावनाएं है।

जहां तक राजस्थान की दलीय व्यवस्था पर प्रभाव का प्रश्न है। यह बसपा के समर्थन में उत्तरोत्तर वृद्धि से स्पष्ट है कि बसपा एक महत्वपूर्ण तीसरी ताकत के रूप में उभर रही है। 1990 के बाद राजस्थान की दलीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धी द्विदलीय व्यवस्था के रूप में उभरी है। इन दोनों प्रतिस्पर्धी दलों में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां है। भारत में जहां गुजरात, मध्यप्रदेश व राजस्थान को छोड़कर शेष भारत में क्षेत्रीय दल नहीं पनप सका है। बसपा का बढ़ता जन समर्थन निश्चय ही यहां की दलीय स्थिति को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा। राजस्थान की प्रतिस्पर्धी द्विदलीय व्यवस्था में यह एक निर्णायक सीमा चिन्ह होगा। बसपा की बढ़ती संभावनाएँ राजस्थान को संक्रमणकालीन स्थिति की ओर ले जाने की ओर संकेत करती है। जहां गठबंधन की राजनीति अस्थिरता की संभावनाएं पैदा होगी। यदि बसपा आने वाले निर्वाचनों में दस प्रतिशत या उससे अधिक जनसमर्थन प्राप्त कर लेती ळे तो ऐसी परिस्थितियां बनने की अधिक संभावनाएं बनती है। बहुजन समाज पार्टी का भी यही लक्ष्य है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आये और सत्ता में भागीदारी करें।

यह प्रश्न बेहद कठिन है कि 'बसपा के जनसमर्थन में विस्तार से भाजपा व कांग्रेस में से किस दल के समर्थन में गिरावट आयेगी और किस सीमा तक आ सकती है यद्यपि प्रथम दृष्टा यह आंकलन किया जा सकता है कि बसपा की पहचान एक दलित पार्टी के रूप में है और उसके विश्वसनीय समर्थन का मुख्य आधार अनुसूचित जातियां है। राजस्थान में राजनीतिक दलों के सामाजिक समर्थन में दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ माना जाता है। अतः बेहद सरल व स्वाभाविक निष्कर्ष यही निकलेगा कि यदि बसपा के समर्थन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तो कांग्रेस का जनसमर्थन घटेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कमजोर होने के पीछे दलित समर्थन का घटना एक मुख्य कारण रहा है। किन्तु यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि राजस्थान में दलितों का उस सीमा तक ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, जितना की उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ में देखा गया है।

सारणी–3.2 : विधानसभा निर्वाचन में प्रमुख दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का विवरण

निर्वाचन वर्ष	कांग्रेस		भाजपा		बसपा	
	मत	विजय	मत	विजय	मत	विजय
1990	33.64	50	40.94	85	2.54	छपस
1993	38.27	76	39.19	95	2.01	छपस
1998	44.95	153	33.91	33	3.81	2
2003	3.65	56	39.85	120	6.40	2
2008	36.92	96	35.60	78	7.66	6
2013	33.68	21	46.031	163	3.48	3

स्त्रोत–राज्य निर्वाचन विभाग से संकलित विभिन्न वर्षों के आंकड़ों के आधार पर।

सारणी–3.3 में बसपा द्वारा आरक्षित व सामान्य सीटों पर पिछले दो निर्वाचनों में प्राप्त जन समर्थन को दर्शाया गया है। इस आधार पर हम बसपा के समर्थन के सामाजिक आधार का विश्लेषण करने का प्रयास कर सकते है। 2003 के निर्वाचन में बसपा ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 34 विधान सभाओं में से 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे और 2.7 प्रतिशत मत प्राप्त किये। 2008 के निर्वाचनों में बसपा ने दलितों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये और 6.1 प्रतिशत मत प्राप्त किये यद्यपि बसपा अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों में से एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई। किन्तु अपने समर्थन में दुगने से अधिक वृद्धि की। यहां यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बसपा ने दलितों के लिए आरक्षित एक भी सीट पर सफलता प्राप्त क्यों नहीं की। जबकि उसने 2003, 2008 व 2013 के निर्वाचनों में जनजाति व सामान्य वर्ग की सीटों पर सफलता प्राप्त की थी। इस प्रश्न को हम सामाजिक अभियांत्रिकी के द्वारा समझ सकते हैं। चूंकि राजस्थान में बसपा अपनी शैशव अवस्था में है और उसके सामाजिक समर्थन की प्रारम्भिक स्थिति समांगी प्रकृति की है जिसके कारण वह दलितों के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में अन्य जातियों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने में असफल रही है। साथ ही यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि दलितों के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में बसपा के इस जनसमर्थन का अधिकांश भाग दलितों से आता है। क्योंकि

बसपा की पहचान प्राथमिक रूप से दलित समर्थक पार्टी के रूप में है। पिछले दो विधान सभा निर्वाचनों में सर्वाधिक वृद्धि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर देखने को मिली है। जो दलितों में बसपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता की और संकेत करती है।

जनजातियों के लिए आरक्षित विधान सभा सीटों पर 2003 के निर्वाचन में 12 प्रत्याक्षी खड़े किये और 2.9 प्रतिशत मत प्राप्त किये। 2008 कि निर्वाचनों में सभी 25 जनजाति सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी खड़े किये और 4.7 प्रतिशत मत प्राप्त किये। 2008 के निर्वाचन में बसपा ने एक सीट पर जीत हासिल की। यद्यपि बसपा ने जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्ग की सीटों की अपेक्षा कम समर्थन प्राप्त किये। इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि जनजातियों में बसपा की स्वीकारोक्ति अन्य वर्गों की अपेक्षा सर्वाधिक कम है। जबकि 2008 के निर्वाचनों में जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर स्वतन्त्र प्रत्याशियों ने लगभग 20 प्रतिशत मत प्राप्त कर चार सीटों पर विजय हासिल की।

सारणी–3.3 विधानसभा निर्वाचन में बसपा की वर्गानुसार सीटों पर प्रदर्शन

	कुल सीट	प्रत्याशी	मत प्रतिशत	विजय
2003 अनु. जाति	34	19	2.7	छपसस
अनु. जनजाति	25	12	2.9	छपसस
2008 अनु. जाति	34	34	6.1	1
अनु. जनजाति	25	25	4.7	छपसस
2013 अनु. जाति	35	35	6.5	छपसस
अनु. जनजाति	25	25	4.9	छपसस

स्त्रोत–राज्य निर्वाचन विभाग से संकलित विभिन्न वर्षों के आंकड़ों के आधार पर

बसपा को सर्वाधिक सफलता सामान्य वर्ग की सीटों पर मिली है। 2003 के विधान सभा निर्वाचन में बसपा ने 93 प्रत्याशी खड़े किये और 4.4 प्रतिशत जनसमर्थन प्राप्त किया। 2003 के निर्वाचन में बसपा ने सामान्य वर्ग की दो सीटों पर राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2008 के निर्वाचन में बसपा ने सामान्य वर्ग की 140 सीटों पर चुनाव लड़ा और आरक्षित वर्ग की सीटों पर बसपा ने समर्थन में लगभग दुगनी वृद्धि दर्ज की गई और 5 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी निर्वाचित हुए। सामान्य वर्ग की सीटों पर बसपा की सफलता में सामाजिक अभियांत्रिकी का योगदान रहा है। सामान्य वर्ग की सीटों पर बसपा प्रत्याशी चयन में सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के सामाजिक ढांचे के प्रति बेहद सजग रही और उस जाति के प्रत्याशी के चयन को प्राथमिकता दी जो उस विधान सभा में बाहुल्य में ही थी। ताकि बाहल्य जाति व दलितों का गठबंधन वांछित सफलता प्राप्त कर सके। चूंकि दक्षिण राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को छोड़कर दलित सभी विधान सभा क्षेत्रों में 20 हजार से 40 हजार मतदाताओं के रूप विद्यमान है।

लोकसभा में बसपा का प्रदर्शन :

लोकसभा निर्वाचनों में बसपा का प्रदर्शन विधानसभा निर्वाचनों की अपेक्षा बहुत कम रहा है। यद्यपि उत्तरोत्तर रूप से इसके समर्थन में वृद्धि हुई है। (सारणी–3.4) राजस्थान में बसपा ने लोकसभा निर्वाचन उम्मीदवार खड़े किये। 1998 में बसपा ने लोकसभा निर्वाचन उम्मीदवार खड़े किये। 1998 के लोकसभा निर्वाचन में बसपा ने 25 सीटों में से 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये और 2.12 प्रतिशत मत प्राप्त किये। 1999 के लोकसभा निर्वाचन में बसपा ने 16 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी घोषित किये और 2.76 प्रतिशत मत प्राप्त किये। इसी प्रकार 2004 के निर्वाचन में बसपा ने 18 उम्मीदवार घोषित किये और 2.9 प्रतिशत मत प्राप्त किये। 2009 के लोकसभा निर्वाचन में बसपा ने पुनः 16 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन में भाग लिया और 3.37 प्रतिशत मत प्राप्त किये। 2014 के लोकसभा चुनाव में 23 उम्मीदवार खड़े किये, जबकि 4.6 प्रतिशत मत प्राप्त किये। लोकसभा निर्वाचनों में कांग्रेस व भाजपा के बाद बसपा ने सीमित मत प्राप्त करने के बावजूद तीसरी शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

सारणी–3.4 लोकसभा निर्वाचन में बसपा का प्रदर्शन

वर्ष	**1998**	**1999**	**2004**	**2009**	**2014**
कुल प्रत्याशी	22	16	18	16	23
प्राप्त मत प्रतिशन	2.12	2.76	2.96	3.37	4.6

स्त्रोत–राज्य निर्वाचन विभाग से संकलित विभिन्न वर्षों के आंकड़ों के आधार पर ।

पिछले तीन विधान सभा व लोकसभा निर्वाचनों में बसपा के प्रदर्शन का तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विधानसभा निर्वाचनों की अपेक्षा लोकसभा निर्वाचनों में बसपा का प्रदर्शन लगभग आधा रह जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है

कि लोकसभा निर्वाचनों में तुलनात्मक प्रदर्शन कमजोर क्यों रहता है? हालांकि इस प्रकार का उत्तर थोड़ा कठिन हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर संगत निष्कर्ष निकाल सकते है। प्रथम, लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से असमान होते है। एक लोकसभा क्षेत्र आठ विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनाया जाता हैं भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार के साथ ही सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हो जाता है। द्वितीय–लोकसभा निर्वाचन संरचना में बसपा बपने प्रत्याशी को जीतने योग्य सामाजिक अभियांत्रिकी के फार्मूले से गैर दलितों का पर्याप्त समर्थन मिल जाता है कि लेकिन लोकसभा निर्वाचन में विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र वे बदली सामाजिक संरचना के कारण गैर दलितों का पर्याप्त समर्थन नगण्य हो जाता है। चतुर्थ–बसपा प्रत्याशी के लोकसभा निर्वाचन में जीतने की न्यून संभावना के कारण बसपा का कुछ दलित वोट अन्य दलों की तरफ चला जाता है। पंचम–विधानसभा क्षेत्र छोटा होने के कारण प्रत्याशी सामाजिक व राजनीतिक रूप से अपना व्यक्तिगत प्रभाव रखता है। जिससे वह अधिक समर्थन हासिल करता है। लेकिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र विस्तृत होने के कारण प्रत्याशी अन्य क्षेत्रों में अपना व्यक्तिगत प्रभाव नहीं रखता है।

अतः इन सभी कारणों का एक स्वाभाविक यह होता है कि एक राजनीतिक दल जो अपने को स्थापित करने की प्रक्रिया में संलग्न हो, विधानसभा निर्वाचनों की अपेक्षा लोकसभा निर्वाचनों में कमजोर प्रदर्शन करता है।

निष्कर्ष :

भारत में राजनीतिक दल की सफलता उसके सामाजिक आधार पर निर्भर करती है। यदि किसी दल को जाति अथवा समाज का सहारा नहीं है तो उसकी सफलता संदिग्ध है। बसपा इस मामले में सौभाग्यशाली है कि उसका अपना स्वयं का सामाजिक आधार है। भारत का दलित वर्ग विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तिशगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात में पार्टी का आधार स्तम्भ है।

राजस्थान में सत्ता में भागीदारी तक पहुँचने के लिए बसपा को दलितों के साथ अन्य समाजों को जोड़ने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के समान ठोस सामाजिक अभियांत्रिकी पार्टी का मत प्रतिशत व सीट बढ़ा सकता है। अतः पार्टी को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है यदि ऐसा हुआ तो बसपा की संभावनाएँ राजस्थान में उज्जवल है।

सन्दर्भ :

1. डा. पी.सी. जाट, "राजस्थान के अप्रमुख राजनीतिक दल"
2. रजनी कोठारी, "भारतीय राजनीति
3. अम्बेध राजन, माई बहुजन समाज (नई दिल्ली ए बी सी डी इ, 1994) पृष्ठ–32
4. बहुजन संगठक– मार्च 9, 1987
5. राजन, माई बहुजन समाज, पृष्ठ–46
6. ऐ.के. वर्मा, "भारतीय लोकतंत्र में समावेशी राजनीति" शोधार्थी, सीएसडीएस नई दिल्ली 8 ' 2006 पृष्ठ–12
7. वहीं पृष्ठ–13
8. बसपा चुनाव घोषणा पत्र 2008
9. अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का साक्षात्कार।
10. अध्यक्ष, भजपा का साक्षात्कार।
11. डा. पी.सी. जाट, "राजनीतिक दल, निर्वाचन एवं मतदान व्यवहार
12. बसपा चुनाव घोषणा पत्र 2013